



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 13, 2016/आश्विन 21, 1938

No. 327]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2016/ASVINA 21, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2016

विषय : चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/37/2016-डीजीएडी.—मै. अतुल लि. (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. और जापान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

- और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह याचिका मै. अतुल लिमिटेड, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र विनिर्माता है, ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता या उसके किसी संबंधित पक्ष द्वारा जॉच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने घोषणा की है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या किसी आयात से संबंधित नहीं हैं।

4. प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता संबंधित नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद 'रेसोरसिनोल' है। इसे रेसोरसिन मेटा-डिहाइड्रोक्सीबेंजीन 1, 3 डिहाइड्रोक्सीबेंजीन या 1, 3 बेंजेनेडिओल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक क्रिस्टलीय, सुगंधित, हाइड्रोस्कोपिक और सफेद ठोस उत्पाद है जो जल में घुलनशील और व्युत्पत्ति के काफी अनुकूल है।

6. संबद्ध वस्तु का प्रयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है जैसे इसका प्रयोग रबड़ उद्योग में रीइनफोर्सिंग सामग्री और रबड़ के बीच एडेशन प्रमोटर के रूप में, सौंदर्य प्रसाधनों में एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में, वुड एडहेसिव रेजिंस में विशेषीकृत थर्मोसेटिंग किया जाता है, विभिन्न प्लास्टिक सामग्री में अनेक हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन प्रकार के अल्ट्रा वायलेट स्टेबलाइजर्स के लिए आरंभिक सामग्री आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि बाजार आसूचना के अनुसार रेसोरसिनोल की 60 प्रतिशतसे अधिक मांग टायरों सहित रबड़ उत्पादों के लिए एडहेसिव रेजिनों में की जाती है।

7. संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्ष 29072100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के आयात अन्य टैरिफ शीर्षों के अधीन भी किए जा रहे हैं। एचएस कोड केवल सांकेतिक है और उत्पाद का वर्णन सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

समान वस्तु

8. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

9. याचिकाकर्ता ने बताया है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु, समान वस्तु है। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित रेसोरसिनोल भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते और कर रहे हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

10. अतः वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

11. वर्तमान जॉच चीन और जापान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह बताते हुए कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है और भारत इस प्रयोजनार्थ सर्वाधिक उचित तुलनीय बाजार है, कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

13. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करते हुए बिक्री, सामान्य और प्रशासनिकव्यय और तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके भारत में उत्पादन लागत के आधार पर जापान में सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया इस जॉच शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

14. आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए एक गौण स्रोत अर्थात् मै. आलइंफो.कॉम से आयात आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए कमीशन, समुद्री भाड़े, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री बीमा और बैंक प्रभार और वैट समायोजन (जहां लागू हों) में कीमत संबंधी समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

16. यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जांच अवधि (पीओआई)

17. याचिकाकर्ताओं ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 (12 महीनों) की जॉच अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि क्षति के विश्लेषण के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 12 से मार्च 13, अप्रैल 13 से मार्च 14, अप्रैल 14 से मार्च 15 और जॉच की प्रस्तावित अवधि के आकड़ों पर विचार किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

20. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को

सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2016

Subject: Anti Dumping investigation concerning imports of resorcinol originating in or exported from China PR and Japan.

No. 14/37/2016-DGAD.—M/s Atul Ltd. (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of resorcinol (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and Japan (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed by M/s Atul Limited, who is the only manufacturer of the product under consideration in India. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party from the subject countries during the period of investigation. Further, petitioner declared that they are not related to either any exporter or producer or any importer of the subject goods from the subject countries

4. The Authority holds that the petitioner constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and also satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

5. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Resorcinol". It is also known as Resorcin Meta-dihydroxybenzene, 1, 3 dihydroxybenzene or 1, 3 benzenediol. It is a crystalline, aromatic, hygroscopic, and white solid product that is water soluble and very conducive to derivatisation.

6. The subject goods are used in various industries like it is used as a adhesion promoter between the reinforcing material and rubber in the rubber industry, antiseptic agents in cosmetics preparations, specialized thermosetting wood-adhesive resins, starting material for a number of hydroxy benzophenone type ultraviolet stabilizers used in various plastic materials etc. The domestic industry has claimed that as per their market intelligence more than 60% of Resorcinol demand is in adhesive resins for rubber products, including tyres.

7. The subject goods are classified under chapter heading 29072100. However, it has been claimed by the petitioner that the subject goods are also being imported under other tariff headings The HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

Like Article

8. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

9. The petitioner has submitted that subject goods produced by the petitioner company and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. Resorcinol produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules.

10. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Country/(ies) involved

11. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR and Japan (referred to as the subject countries).

Normal Value

12. The Petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules. The petitioner has claimed normal value on the basis of cost of production in India considering international prices of raw material, duly adjusted; stating that information on cost or price in a market economy third countries is not publically available and India is the most appropriate comparable market for the purpose.

13. Further, the Petitioner has also constructed the normal value in Japan on the basis of cost of production in India considering the international price of the raw material, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit. The Authority has *prima-facie* considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation.

Export Price

14. The applicant has determined export price using import data from secondary source, i.e., M/s Allinfo.com., to assess the volume and value of imports of subject goods in India. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, and bank charges and Vat adjustment (where applicable) to arrive at the net export price.

Dumping Margin

15. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margin is estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

16. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed, and cash flow to the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation (POI)

17. Petitioner has proposed the period from 1st April 2015 to 31st March 2016 (12 months) as the period of investigation. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014, April 2014 to March-2015 and the proposed period of investigation has been considered.

Submission of information

18. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

20. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

23. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

24. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority